>

Title: Need to ensure proper use of Central fund in welfare schemes for Adivasis in naxal affected districts of Madhya Pradesh.

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, देश में नक्सल प्रभावित जिलों में 178 सैनिकों की मौत के बाद भारत सरकार ने यह तय किया था कि बहुउद्देशीय विकास परियोजना जिलों के कलैक्टर के माध्यम से नक्सल प्रभावित जिलों में चलाई जाएं। भारत सरकार के प्रस्ताव पर प्लानिंग कमीशन ने 1500 करोड़ रुपये, जिसमें हर जिले को 55 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस पैसे पर कलैक्टर का सीधा नियंत्रण था जो कुछ निर्धारित कामों जैसे स्कूल बिल्डिंग, आंगनवाड़ी भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि पर खर्च होने थे। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में यह पैसा मुख्य मंत्री के कार्यक्रमों को आयोजित करने एवं ग्राम ओलम्पियार्ड आदि करा कर अपनी पार्टी भर का प्रचार किया। ...(व्यवधान) आप सुनिए, यह बहुत गंभीर आरोप है। उदाहरण के लिए डिंडोरी नक्सल प्रभावित जिले में साढ़े सात लाख रुपये आंगनवाड़ी भवन के लिए दिए जो दो वर्ष में तैयार नहीं हो सका। पीडब्ल्यूडी के सीएसआर रेट के हिसाब से 4 लाख रुपये में भवन बनना चाहिए था। यह पैसा तुंत एवं निश्चित अवधि में खर्च करना था, जबकि तत्कालीन कलैक्टर अपना हिस्सा लेकर दूसरे जिले में पदस्थ हो गए। काम आज भी अधूरा है। केवल एक एनजीओ प्रधान को एक-चौथाई काम एलॉट कर दिया गया जो आज भी अधूरा है। प्रदेश के अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में भी कमतर यही स्थिति है।

महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध है कि भारत सरकार तुंत हस्तक्षेप कर, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आदिवासियों को नक्सली प्रभाव से उबारने में भेजी गई राशि के दुरुपयोग से रोक कर, गरीब आदिवासियों की बेहतरी में मदद करें।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **